

माननीय न्यायालय राजीव भल्ला और डॉ. भारत भूषण परसून, जे. जे.

जैस्मर सिंह-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाता

2011 का एल. पी. ए. 2245 सितम्बर 19, 2014

लेटर्स पेटेंट, 1919-चैप्टर X-लेटर्स पेटेंट अपील-लेबर लॉ-इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947-S.25-B-एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती-कर्मचारी-अपीलार्थी ने दावा किया कि दो अलग-अलग उप-मंडलों में दैनिक मजदूरी पर रोजगार की गणना करके इस समाप्ति की तारीख से 240 दिन पहले पूरा कर लिया है-कर्मचारी-अपीलार्थी ने आगे दावा किया कि एक उप-मंडल में उसके कार्य दिवसों के साथ-साथ मस्टर रोल को भी नजरअंदाज कर दिया गया है-आयोजित, कर्मचारी-अपीलार्थी-कर्मचारी-अपीलार्थी दोनों के खिलाफ तथ्य और कानून ने स्वेच्छा से एक उप-मंडल में नौकरी छोड़ दी थी एक नए उप-मंडल में शामिल होने के लिए और दोनों उप-मंडलों में नियुक्ति प्राधिकरण अलग और अलग था-इसके अलावा, दो उप-मंडलों में नौकरी की प्रकृति भी अलग थी-इसलिए, एक उप-मंडल में दी गई सेवा को दूसरे उप-मंडल में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए-अपीलार्थी ने याचिका दायर करने के आदेश को खारिज कर दिया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी ने 240 दिन पूरे कर लिए हैं, उप-मंडल संख्या 8 और उप-मंडल संख्या 6 में भी इस आधार पर दैनिक मजदूरी पर रोजगार की गणना की है कि कार्यकारी अभियंता i.e., दोनों उप-प्रभागों के दैनिक मजदूरों के प्राधिकारी की नियुक्ति और बर्खास्तगी i.e. No.8 और No.6 समान थे। उक्त पुरस्कार को चुनौती देने वाले उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका में, एकल न्यायाधीश ने रिकॉर्ड i.e पर एक त्रुटि देखी थी। उप-मंडल संख्या. 8 और संख्या. 6 स्वतंत्र कार्यालय थे जो अलग-अलग थे और अलग-अलग थे क्योंकि ये अलग-अलग श्रम बल को नियोजित कर रहे थे और विभिन्न कार्यकारी अभियंताओं के प्रशासनिक नियंत्रण में भी थे। (para 5)

आगे कहा गया है कि जब उत्तरदाताओं के कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रस्तुत दोनों शपथपत्रों की प्रासंगिक मस्टर रोल (Ex.WX) के इंटरफेस में जांच की जाती है, तो कोई भ्रम नहीं रहता है कि अपीलार्थी/कर्मचारी ने उप-मंडल नं। 8 अगस्त, 1993 तक और वास्तव में कुल मिलाकर केवल 231 दिनों के लिए काम किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और सितंबर, 1993 में कहीं उप-मंडल संख्या 6 में अपनी नई नौकरी में शामिल हो गए थे और दिसंबर, 1993 तक कुल 96 दिनों तक वहां काम किया था। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत मस्टर रोल (Ex.WX) उप-मंडल संख्या 6 से संबंधित है न कि उप-मंडल संख्या 8 से। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित फैसले में इन तथ्यों पर ध्यान दिया था। तैयार संदर्भ के लिए आक्षेपित निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार संलग्न किया गया है:

“कर्मचारी ने दलील दी कि उसने उपखंड संख्या में 310 दिनों तक काम किया था। 8 और 6 जब एक साथ लिया जाता है। यह कामगार का मत था कि ये दोनों उप-मंडल एक ही अधिकारी के अधीन थे और इसलिए, इन दोनों उप-मंडलों में उनके द्वारा बिताई गई अवधि को एक साथ लिया जाना था और उन दिनों की ओर गिना जाना था, जिनके दौरान कामगार ने अपनी सेवा की समाप्ति की तारीख से पिछले 12 महीनों में सेवा की थी, जबकि प्रबंधन ने एमडब्ल्यू-1 विपिन शर्मा, एसडीओ की जांच की, जिन्होंने कहा था कि कामगार को उप-मंडल संख्या में नियुक्त किया गया था। 8 जनवरी, 1993 से अगस्त, 1994 तक मस्टर रोल दैनिक मजदूरी के आधार पर और इसके बाद उन्होंने खुद काम छोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा कि अक्टूबर, 1993 से दिसंबर, 1993 तक, कामगार ने किसी अन्य उपखंड नं. 8. उप-मंडल नं। 6, कमल, जहां मजदूर ने अक्टूबर, 1993 से दिसंबर, 1993 तक अपने कर्तव्यों का पालन किया, सड़क और पुल के निर्माण का काम कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप

से कहा है कि उप-मंडल नं. 6 और उप-मंडल नं. 8 अलग-अलग कार्यकारी अभियंताओं के अधीन है और काम की प्रकृति भी दो उपखंडों से अलग है। उन्होंने आगे कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव का काम डिवीजन नं. 8 वह है जो भारत सरकार के भूतल मंत्रालय द्वारा सौंपा गया है। कर्मचारी ने स्वेच्छा से सितंबर, 1993 में नौकरी छोड़ दी और नए उप-मंडल नं. 6 अक्टूबर, 1993 में जहां उन्होंने दिसंबर, 1993 तक काम करना जारी रखा। इसलिए, यह याचिकाकर्ता-प्रबंधन का विशिष्ट रुख था कि दो उप-मंडलों की नियुक्ति प्राधिकरण अलग-अलग एक्सईएन थे और आगे उक्त उप-मंडलों के काम की प्रकृति अलग थी, जो उनके द्वारा की जा रही थी। यह कामगार का मामला नहीं है कि उसकी सेवाओं को डिवीजन नं. 8 से डिवीजन संख्या 6, जिसके अनुपालन में, वह उप-डिवीजन संख्या में अपने कर्तव्यों में शामिल हो गए थे। 6 उपखंड नं. 8. ऐसा होने पर, प्रबंधन का रुख पूरी तरह से न्यायोचित है और इस प्रकार, श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।”

इन विद्वानों के निष्कर्ष एकल न्यायाधीश को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तथ्य और कानून दोनों ही अपीलार्थी के खिलाफ हैं। (Para 9)

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता आभा रतबोरे।

प्रतिवादियों की ओर से हरियाणा की सहायक महाधिवक्ता ममता सिंगला तलवार।

डॉ. भरत भूषण पारसन, जे.

- 1) लेटर्स पेटेंट के खंड x के अधीन इस लेटर्स पेटेंट अपील में, 2001 के सीडब्ल्यूपी संख्या. 9532 में दिनांक 7.4.2010 के विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी गई है।
- 2) निर्णय का आक्षेप करते हुए, अपीलार्थी/कर्मकार के वकील का दावा है कि उप-मंडल संख्या 6 के कार्य दिवसों के होते हुए भी उप-मंडल संख्या 8 में रोजगार में उसके 253 दिन जनवरी, 1993 से सितंबर, 1993 तक पूरे होने के तथ्य को आक्षेपित निर्णय में नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ। यह भी दावा किया जाता है कि एकल न्यायाधीश इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि अपीलार्थी ने सितंबर, 1993 (श्रम न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूएक्स प्रदर्शित करें) के लिए मस्टर रोल भी प्रस्तुत किया था, जिसमें दिखाया गया है कि उसने उक्त महीने के लिए 22 दिनों तक काम किया था।
- 3) यह दावा करते हुए कि उसने अपनी समाप्ति की तारीख से पहले 240 दिन पूरे कर लिए थे और इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 25-एफ का उल्लंघन हुआ था, अपीलार्थी आक्षेपित निर्णय को वापस लेने, श्रम न्यायालय के पुरस्कार (अनुलग्नक पी-4) की बहाली और सेवा की निरंतरता और पूर्ण वेतन के साथ बहाली के लिए प्रार्थना करता है।
- 4) कागजी किताब को देखते हुए पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना गया है।
- 5) औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी ने 240 दिन पूरे कर लिए हैं, उप-मंडल संख्या. 8 और उप-मंडल संख्या. 6 में भी इस आधार पर दैनिक मजदूरी पर रोजगार की गणना की कि कार्यकारी अभियंता i.e. दोनों उप-मंडलों के दैनिक मजदूरों की नियुक्ति और बर्खास्तगी प्राधिकरण i.e. No.8 और No.6 समान थे। उक्त पुरस्कार को चुनौती देने वाले उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका में, एकल न्यायाधीश ने रिकॉर्ड i.e पर एक त्रुटि देखी थी। उप-मंडल संख्या. 8

और संख्या. 6 स्वतंत्र कार्यालय थे जो अलग-अलग थे और अलग-अलग थे क्योंकि ये अलग-अलग श्रम बल को नियोजित कर रहे थे और विभिन्न कार्यकारी अभियंताओं के प्रशासनिक नियंत्रण में भी थे।

- 6) अपीलार्थी/कर्मचारी की याचिका कि ऐसा निष्कर्ष रिट याचिका में दर्ज नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह मामले के तथ्यों से संबंधित है, एक गलत नाम है। विवादित पुरस्कार में स्पष्ट दोषों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विवादित आदेश पारित करते समय प्रबंधन की रिट याचिका पर निर्णय लेने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई मछली पकड़ने का अभियान नहीं चलाया गया है।
- 7) विद्वत एकल न्यायाधीश के स्पष्ट निष्कर्ष का सामना करते हुए कि अपीलार्थी की याचिका, जिसने अपनी समाप्ति की तारीख से पहले 12 महीनों में 240 दिनों से अधिक की अवधि पूरी कर ली है, उप-मंडल रोजगार संख्या 8 और 6 में अपने दैनिक मजदूरी रोजगार को एक साथ लेना तथ्यात्मक रूप से गलत है, अपीलार्थी एक नया रुख लेकर आया है कि भले ही उसका उप-मंडल संख्या 6 में रोजगार हो। 8 को अकेले 240 दिनों की अवधि की गणना के लिए लिया जाता है, यह वैधानिक अवधि से अधिक है, यदि उसकी समाप्ति की तारीख से पीछे गिना जाता है। इस पहलू की जांच करने के बाद, 10.4.2013 को इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें उत्तरदाताओं से अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“कुछ समय के लिए पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम महसूस करते हैं कि चूंकि इस बारे में विवाद है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त उपखंड में 240 दिनों तक काम किया था या नहीं, इसलिए प्रत्यर्थी-राज्य को उपखंड की मस्टर रोल द्वारा समर्थित एक हलफनामा दाखिल करने दें।”

- 8) प्रत्यर्थी द्वारा दायर हलफनामे की जांच पर, उत्तरदाताओं से दिनांक 2.7.2013 के आदेश के माध्यम से एक और स्पष्टीकरण मांगा गया था। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“श्रम न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल लिखित कथन और दिनांक 20.5.2013 के शपथपत्र के बीच स्पष्ट संघर्ष प्रतीत होता है। 'पंक्ति उत्तरदाताओं ने, इसलिए, इस अस्पष्टता को स्पष्ट करने का निर्देश दिया, और पूर्व का मूल भी प्रस्तुत किया। सुनवाई की अगली तारीख पर डब्ल्यूएक्स ”

- 9) जब उत्तरदाताओं के कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रस्तुत दोनों शपथपत्रों की प्रासंगिक मस्टर रोल (उदा. (क) अपीलार्थी/कर्मचारी ने अगस्त, 1993 तक उप-मंडल संख्या. 8 में कार्य किया था और वास्तव में कुल मिलाकर केवल 231 दिनों के लिए कार्य किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और सितंबर, 1993 में वहीं उप-मंडल संख्या 6 में अपनी नई नौकरी में शामिल हो गए थे और दिसंबर, 1993 तक कुल 96 दिनों तक वहां काम किया था। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत मस्टर रोल उप-मंडल संख्या. 6 से संबंधित है न कि उप-मंडल संख्या. 8 से। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित फैसले में इन तथ्यों पर ध्यान दिया था। तैयार संदर्भ के लिए आक्षेपित निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार संलग्न किया गया है:

“कर्मचारी ने निवेदन किया कि उसने उपखंड संख्या में 3.10 दिनों के लिए काम किया था। 8 और 6 जब एक साथ लिया जाता है। यह कामगार का मत था कि ये दोनों उप-मंडल एक ही अधिकारी के अधीन थे और इसलिए, इन दोनों उप-मंडलों में उसके द्वारा बिताई गई अवधि को एक साथ लिया जाना था और उन दिनों की ओर गिना जाना था, जिनके दौरान कामगार ने अपनी सजा की समाप्ति की तारीख से पिछले 12 महीनों में सजा सुनाई थी, जबकि प्रबंधन ने एमडब्ल्यू-1 विपिन शर्मा, एसडीओ की जांच की। जिसने निर्धारित किया था कि कामगार को उप-मंडल नं. 8 जनवरी, 1993 से अगस्त, 1994 तक मस्टर रोल दैनिक मजदूरी के आधार पर और इसके बाद उन्होंने खुद काम छोड़ दिया। 1।e ने आगे कहा कि अक्टूबर, 1993 से दिसंबर, 1993 तक, कर्मचारी ने किसी अन्य उपखंड के साथ काम किया, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग i.e. में नहीं आता है। अनुमंडल नं. 8. उप-मंडल नं. 6 कमल, जहाँ

मजदूर ने अक्टूबर से अपने कर्तव्यों का पालन किया। 1993 से दिसंबर। 1993, सड़क और पुल के निर्माण का काम कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उप-मंडल नं. 6 और उप-मंडल नं. 8 अलग-अलग कार्यकारी अभियंताओं के अधीन है और काम की प्रकृति भी दो उप-दृष्टि से अलग है, आयोग ने आगे कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव कार्य डिवीजन नं. 8 वह है जो भारत सरकार के भूतल मंत्रालय द्वारा सौंपा गया है। कर्मचारी ने स्वेच्छा से सितंबर, 1993 में नौकरी छोड़ दी और नए उप-मंडल नं. 6 अक्टूबर, 1993 में जहां उन्होंने दिसंबर, 1993 तक काम करना जारी रखा। इसलिए, यह याचिकाकर्ता-प्रबंधन का विशिष्ट रुख था कि दो उप-मंडलों की नियुक्ति का अधिकार अलग था और आगे उक्त उप-मंडलों के काम की प्रकृति अलग थी, जो उनके द्वारा की जा रही थी। यह कामगार का मामला नहीं है कि उसकी सेवाओं को डिवीजन नं. 8 से डिवीजन नं. 6, जिसके अनुपालन में, वह उप-मंडल संख्या में अपने कर्तव्यों में शामिल हुए थे। 6 उपखंड नं. 8. ऐसा होने पर, प्रबंधन का रुख पूरी तरह से न्यायोचित है और इस प्रकार, श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।”

इन विद्वानों के निष्कर्ष एकल न्यायाधीश को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती थी, तथ्य और कानून दोनों अपीलार्थी के खिलाफ मृत हैं।

10) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में तथ्य या कानून की कोई त्रुटि नहीं होने के कारण, योग्यता से रहित होने के कारण अपील खारिज कर दी जाती है।

राजीव भल्ला, जे। मैं सहमत हूँ।

**अस्वीकरण :** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

*कार्तिक शर्मा*

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

*नूह, हरियाणा*